



CURRENT AFFAIRS

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

DATE: 26-08-25







The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE Tuesday, 26 Aug, 2025

Edition: International Table of Contents

Page 04	भारत और फिजी ने खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र का आह्वान किया,
Syllabus: GS 2: International	रक्षा संबंधों को गहरा करने पर सहमति जताई
Relations	
Page 06	स्टील्थ फ्रिगेट उदयगिरि और हिमगिरि आज नौसेना में शामिल
Syllabus: GS 3: Science and	होंगे
technology / Prelims	
Page 08	बहस से परे: विधायिकाओं की निष्क्रियता कार्यपालिका में
Syllabus: GS 2: Indian Polity	शक्तियों के संकेंद्रण के कारण है
Page 08	मित्र और शत्रु: पाकिस्तान, बांग्लादेश से भारत के अलगाव से
Syllabus: GS 2: International	पैदा हुए खालीपन को भर रहा है
Relations	
Page 09	लगभग 30% सांसदों और विधायकों पर गंभीर आपराधिक
Syllabus : GS 2 : Indian Polity	मामले दर्ज हैं
Page 08 : Editorial Analysis	नया संविधान विधेयक, संतुलन की आवश्यकता
Syllabus: GS 2: Indian Polity	





Page 04: GS 2: International Relations

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिजी के प्रधानमंत्री सिटीवेनी राबुका की नई दिल्ली में हुई मुलाकात भारत की इंडो-पैसिफिक नीति के लिए महत्त्वपूर्ण है। चीन की प्रशांत द्वीपों में बढ़ती सॅक्रियता के बीच यह बैठक भारत और फिजी के बीच सामरिक, समुद्री और विकासात्मक सहयोग को नई दिशा देती है।

बैठक की प्रमुख बातें

1. समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग

- भारत फिजी की सेनाओं को प्रशिक्षण, उपकरण और क्षमता निर्माण में मदद देगा।
- संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों, सैन्य चिकित्सा तथा श्वेत शिपिंग सूचना आदान-प्रदान पर सहमति बनी।
- स्वा (फिजी की राजधानी) में भारतीय उच्चायोग में रक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना और दो एम्ब्लेंस का उपहार।

2. मुक्त और समावेशी इंडो-पैसिफिक की दृष्टि

- दोनों देशों ने मुक्त, खुले, समावेशी और सुरक्षित इंडो-पैसिफिक का समर्थन किया।
- भारत की इंडो-पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव (IPOI) को फिजी ने स्वागत किया।

यह कदम चीन की सैन्य उपस्थिति बढाने की योजनाओं के संतुलन का संकेत है।

विकासात्मक सहयोग

- सात समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर, जिनमें फिजी में सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल निर्माण और प्रवास व गतिशीलता समझौता शामिल।
- साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना पर सहमति।

4. भूराजनीतिक संदर्भ

- फिजी, दक्षिण प्रशांत में सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है और इसने चीन के नौसैनिक अड्डे की योजनाओं का विरोध किया था।
- भारत-फिजी साझेदारी, भारत को प्रशांत द्वीपों में एक विश्वसनीय सहयोगी और संतुलनकारी शक्ति के रूप में स्थापित करती है।

India, Fiji call for open Indo-Pacific region, agree to deepen defence ties

As per a joint statement, both the sides emphasise the importance of their 'shared interests in advancing regional peace,

Kallol Bhattacherjee

ndia will provide train-ing and equipment to upgrade Fiji's mari-e security, Prime Miniser Narendra Modi said on

wetcoming visting Fi-jian Prime Minister Sitiveni Rabuka, Mr. Modi said In-dia and Fiji "strongly sup-port a free, open" Indo-Pacific region as both sides declared that India would work to build capacity for the armed forces of Fiji.

"In our cooperation with the Pacific island nations, we see Fiji as a hub Both our countries strong ly support a free, open, in clusive, secure, and prosperous Indo-Pacific. We warmly welcome In-dia's Indo-Pacific Oceans Initiative," Mr. Modi said, announcing the collabora-tion between India and the Fijian military forces. A joint statement issued at the end of consultation



supporting Fiji's strategic priorities in these areas,' the joint statement said. said the two sides empha-sised the importance of their "shared interests in advancing regional peace, stability, and prosperity". "Prime Minister Modi reaffirmed India's commit-

ment to advancing the ment to advancing the priority areas of coopera-tion outlined in the Memo-randum of Understanding [MoU] on Defence Cooper-ation signed in 2017, and to

Speaking on the occasion, Mr. Rabuka emphasised the need to protect Fiji's Exclusive Economic Zone, and welcomed India's assurance to assist with Fiji's security needs. "Prime Minister Rabuka welcomed the planned port call by an Indian naval ship to Fiji which will enhance maritime cooperation and interoperability." Welcomes India's aid Welcomes India's aid
The two sides agreed to
work together on UN peacekeeping operations, military medicine, the White
Shipping Information Exchange, and capacity-building for Fijian military

During the talks at Hyd-erabad House here, India and Fiji signed seven MoUs that included an agree-ment on building a super-specialty hospital in Fiji, and one on migration and mobility. Both the leaders mobility. Both the leaders agreed to strengthen cooperation against terrorism, and reiterated condemnation for the terror attack in Pahalgam. Mr. Modi announced the gifting of two ambulances to Fiji's military forces, and the opening of the defence wing in the High Commission of the dia in Fijian capital Suva The countries agreed to enhance cooperation in cy-bersecurity, and wel-comed the setting up of a cybersecurity training cell in Fiji.

Mr. Rabuka had in July opposed China's reported

Mr. Rabuka had in July opposed China's reported plans to establish a naval base in the Pacific islands. As a signal to the Chinese side, the statement also called for a "free, open In-do-Pacific region".



VISHV UMIYA FOUNDATION INSTITUTE FOR CIVIL SERVICES (VUFICS)





भारत के लिए महत्व

- सामरिक विस्तार हिंद महासागर से आगे प्रशांत में भारत की उपस्थिति मजबूत।
- चीन का संतुलन प्रशांत द्वीपों को जोड़कर भारत क्षेत्र में चीन की सक्रियता का विकल्प प्रस्तुत करता है।
- सॉफ्ट पावर और कूटनीति अस्पताल पिरयोजना, चिकित्सा सहायता और प्रवास समझौते भारत की सकारात्मक छिव बढ़ाते हैं।
- समुद्री सुरक्षा छोटे द्वीप देशों के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZs) की निगरानी में सहयोग।

निष्कर्ष

भारत–िफजी रक्षा और विकास साझेदारी न केवल द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करती है बल्कि इंडो–पैसिफिक में भारत की समग्र रणनीति को भी सुदृढ़ करती है। सुरक्षा सहयोग को विकासात्मक सहायता के साथ जोड़कर भारत स्वयं को एक संतुलित और भरोसेमंद साझेदार के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में यह सहयोग सामूहिक क्षेत्रीय स्थिरता और शांति सुनिश्चित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है।

UPSC Prelims Practice Question

Ques: फिजी भौगोलिक रूप से प्रशांत महासागर के किस द्वीप समूह का हिस्सा है?

- (a) पॉलिनेशिया
- (b) मेलानेशिया
- (c) माइक्रोनेशिया
- (d) ऑस्ट्रेलेशिया

Ans: (b)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न : भारत और फिजी द्वारा "स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी और सुरक्षित इंडो-पैसिफिक" पर बल देना, प्रशांत द्वीपों में चीन की बढ़ती उपस्थिति के प्रति संतुलित प्रतिक्रिया माना जाता है। आलोचनात्मक मुल्यांकन कीजिए। **(250 शब्द)**





Page 06: GS 3: Science and technology / Prelims

भारत ने प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट्स आईएनएस उदयगिरि और आईएनएस हिमगिरि को विशाखापट्टनम में नौसेना में शामिल किया। यह पहली बार है जब दो अत्याधुनिक युद्धपोत अलग-अलग शिपयार्ड्स में बने और एक साथ नौसेना में शामिल हुए। यह भारत की बढ़ती स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमता और हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में नौसेना की शक्ति को दर्शाता है।

प्रमुख बिंदु

Stealth frigates *Udaygiri*, *Himgiri* to join Navy today

The vessels are follow-on variants of Shivalik-class frigates; they have advanced weaponry, modern sensor systems designed to execute full spectrum of maritime operations in blue-water conditions

Saurabh Trivedi

he Indian Navy is set to commission the state-of-the-art Project 17A stealth frigates *Udaygiri* and *Himgiri* at the Naval Base in Visakhapatnam on Tuesday.

Defence Minister Rajnath Singh will preside over the event, which will mark the first-ever simultaneous commissioning of two frontline warships built at different shipyards.

Enhanced capability

Mr. Singh said that both vessels were follow-on variants of the Shivalik-class frigates. They featured enhanced stealth capabilities, advanced weaponry, and modern sensor systems designed to execute the full spectrum of maritime operations in bluewater conditions. Udaygiri, built by Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. in Mumbai, and Himgiri, constructed by Garden Reach Shipbuilders & Engineers



Ready to serve: INS Udaygiri during its launch at Mazgaon Docks Limited in Mumbai in May 2022. PTI

(GRSE) in Kolkata, showcase India's growing shipbuilding expertise and inter-yard collaboration. Notably, *Udaygiri* was the fastest of her class to be delivered after launch, owing to the adoption of modular construction techniques.

Designed in-house by the Navy's Warship Design Bureau (WDB), *Udaygiri* is the 100th vessel to be designed, marking a milestone in five decades of indigenous warship design. Both frigates are fitted with combined diesel or gas (CODOG) propulsion, an integrated platform management system, and advanced Indian-made weapons and sensors. With nearly 75% indigenous con-

tent – supported by several MSMEs – the ships embody the vision of Aatmanirbhar Bharat, the Ministry added.

Reviving the heritage of earlier warships that bore these names, the new frigates will now join the Eastern Fleet, substantially enhancing the Navy's reach in the Indian Ocean.

1. प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट्स

- शिवालिक-श्रेणी फ्रिगेट्स के उन्नत संस्करण।
- बेहतर स्टेल्थ क्षमता, आधुनिक हथियार और सेंसर सिस्टम से लैस।
- उदयगिरि नौसेना की वारिशप डिज़ाइन ब्यूरो (WDB) द्वारा डिज़ाइन किया गया 100वाँ स्वदेशी पोत है।

2. निर्माण एवं स्वदेशी योगदान

- आईएनएस उदयगिरि : मझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL), मुंबई द्वारा निर्मित।
- आईएनएस हिमगिरि : गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), कोलकाता द्वारा निर्मित।
- लगभग 75% स्वदेशी सामग्री, जिसमें अनेक MSMEs का सहयोग।





• मॉड्यूलर निर्माण तकनीक अपनाने से निर्माण समय घटा (उदयगिरि सबसे तेज़ तैयार हुआ)।

3. प्रौद्योगिकीय विशेषताएँ

- CODOG (Combined Diesel or Gas) प्रणोदन प्रणाली।
- इंटीग्रेटेड प्लेटफ़ॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम, भारतीय हथियार एवं सेंसर।
- ब्लू-वॉटर क्षमता : दूरगामी समुद्री अभियानों में सक्षम।

4. रणनीतिक महत्व

- पूर्वी बेड़ा (Eastern Fleet) को मजबूती मिलेगी → व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा व हिंद महासागर में चीन की उपस्थिति का संतुलन।
- अंतर-शिपयार्ड सहयोग से भारत के जहाज निर्माण उद्योग को प्रोत्साहन।
- पहले के समान नाम वाले युद्धपोतों की परंपरा को पुनर्जीवित किया गया।

निष्कर्ष

आईएनएस उदयगिरि और आईएनएस हिमगिरि का शामिल होना भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल में एक अहम कदम है। उन्नत स्टेल्थ तकनीक, स्वदेशी डिज़ाइन और ब्लू-वॉटर क्षमताओं के साथ ये पोत भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेंगे, SAGAR (Security and Growth for All in the Region) की दृष्टि को आगे बढ़ाएँगे और भारत को हिंद-प्रशांत में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में स्थापित करेंगे।

UPSC Prelims Practice Question

Ques: प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- 1. ये शिवालिक-श्रेणी फ्रिगेट्स के उन्नत संस्करण हैं।
- 2. इनका डिज़ाइन भारतीय नौसेना के वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो (WDB) ने किया है।
- 3. इनका निर्माण पूर्णतः आयातित हथियारों और प्रणालियों से किया गया है। उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

Ans: (a)





Page: 08: GS 2: Indian Polity

संसद और राज्य विधानसभाएँ भारत की प्रतिनिधिक लोकतंत्र की आधारशिला हैं। इनका मूल कार्य – कानून बनाना, कार्यपालिका पर निगरानी रखना तथा विचार–विमर्श करना – लगातार कमजोर होता जा रहा है। बार-बार के स्थगन, बिना बहस

विधेयकों का पारित होना और बैठक दिनों की कमी लोकतांत्रिक संकट को उजागर करती है। हाल ही में 18वीं लोकसभा मात्र 29% निर्धारित समय ही चली, जो अब तक का सबसे कम है।

मुख्य कारण

1. कार्यपालिका में शक्ति का केंद्रीकरण

- प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों का अत्यधिक प्रभुत्व।
- 2024 में राज्य विधानसभाओं की औसत बैठक केवल 20 दिन (2017 में 28 दिन थी)।

2. विधायी जाँच-पडताल में गिरावट

- आधे से अधिक विधेयक एक ही दिन पारित।
- प्रश्नकाल अप्रभावी लोकसभा में केवल 8% और राज्यसभा में 5% प्रश्नों के मौखिक उत्तर मिले।

3. संस्थागत कमजोरी

- 2019 से लोकसभा में उपाध्यक्ष नहीं; 8 राज्य विधानसभाओं में भी यही स्थिति।
- संसदीय सिमतियाँ, जो पहले गंभीर विचार का मंच थीं, अब पक्षपात से ग्रस्त।

4. विपक्ष की भूमिका का क्षरण

- संवादं और सहमति का अभाव।
- बहस की जगह हंगामा व स्थगन, जिसके कारण विधायी कार्य प्रभावित।

प्रभाव

- लोकतांत्रिक घाटा पारदर्शिता और जवाबदेही कमजोर।
- नीति अक्षमता बिना बहस बने कानून लागू करने में कठिनाई।
- जन विश्वास में कमी जनता को विधानमंडल "विवाद का रंगमंच" लगता है।
- संघीय ढाँचे पर असर राज्यों में कम बैठक से जवाबदेही और घटती है।

आगे की राह

1. संस्थागत सुधार

- संसद व विधानसभा के लिए न्यूनतम बैठक दिन तय (जैसे संसद 100 दिन, राज्य – 50 दिन)।
- महत्वपूर्ण विधेयकों को समितियों को भेजना अनिवार्य।

Beyond debate

<u>Dysfunction of legislatures is due to</u> concentration of power in the executive

ddressing the two-day All India Speakers' Conference in New Delhi on August 24, Union Home Minister Shah called attention to the frequent disruptions that have paralysed deliberations in Assemblies and Parliament. His point that "debate must take place in a democracy" is beyond any debate. But when one goes beyond the truism, a picture of India's representative democracy in distress emerges. Bitterness between the government and the Opposition has erased the scope for any common ground, and Parliament has been reduced to a theatre of mutual diatribe. His remarks followed soon after the Opposition's protests, demanding a debate on the Special Intensive Revision of electoral rolls in Bihar, that led to repeated adjournments. Most of the legislative business was carried out with little or no debate. In a session with 21 sittings spread out over 32 days, 15 Bills were passed. According to PRS Legislative Research's analysis, the Lok Sabha functioned for 29% of its scheduled time, and the Rajya Sabha for 34% the lowest functioning seen during the 18th Lok Sabha. Two-thirds of the planned time was lost to repeated adjournments. In the Lower House, only 8% of starred questions received an oral reply, while it was 5% in the Upper House. On 12 days in the Rajya Sabha and on seven in the Lok Sabha, no questions were answered orally over the 21 days. Question Hour, an instrument of executive accountability, has been rendered ineffective.

The dysfunction of legislatures is linked to concentration of power in the chief executive, the Prime Minister and Chief Ministers. According to the Annual Review of State Laws 2024 by PRS Legislative Research, State Assemblies met for an average of just 20 days in 2024, down from 28 in 2017. Larger States such as Uttar Pradesh and Madhya Pradesh recorded only 16 sitting days, while Odisha and Kerala led with 42 and 38 days, respectively. More than half the Bills were passed on the same day, with little debate. Eight Assemblies do not have a Deputy Speaker; the Lok Sabha has not had a Deputy Speaker since June 2019. Parliamentary committees that used to be a platform for more deliberative and less acrimonious debates have also become vulnerable to partisanship. It is propitious that Mr. Shah thinks that there should be more debate in legislatures, but it will be meaningful only when the government translates that view into action by engaging with the Opposition. A starting point can be a consensus election of an Opposition leader as the Deputy Speaker of the Lok Sabha.





2. विपक्ष की भूमिका सुदृढ़ करना

- उपाध्यक्ष का चुनाव परंपरा अनुसार विपक्ष से।
- राष्ट्रीय मुद्दों पर सर्वसम्मति का वातावरण।

3. प्रश्नकाल और समितियों को पुनर्जीवित करना

- प्रश्नकाल अबाधित रूप से चले।
- समितियों को पक्षपात से मुक्त कर गंभीर विमर्श का मंच बनाना।

4. व्यवहारिक और राजनीतिक सुधार

- बार-बार व्यवधान पर कडे नियम।
- विवादास्पद मुद्दों पर संरचित बहस।

निष्कर्ष

विधानमंडलों की अव्यवस्था क्षमता की कमी नहीं बल्कि शक्ति के केंद्रीकरण और राजनीतिक अनिच्छा का परिणाम है। जैसा कि गृहमंत्री ने कहा – "लोकतंत्र में बहस होनी ही चाहिए" – लेकिन यह तभी सार्थक होगी जब सरकार वास्तविक संवाद की इच्छा दिखाए, विपक्ष को सम्मानजनक भूमिका दे और संसदीय परंपराओं को पुनः जीवित करे। मजबूत विधानमंडल ही भारत के लोकतांत्रिक भविष्य और सुशासन की गारंटी हैं।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: भारतीय विधानमंडलों की बढ़ती अव्यवस्था कार्यपालिका में शक्ति के केंद्रीकरण से गहराई से जुड़ी हुई है। इस प्रवृत्ति के कारणों और परिणामों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। भारत में विचार-विमर्शात्मक लोकतंत्र को पुनः स्थापित करने हेतु सुधारों का सुझाव दीजिए। (250 शब्द)





Page 08 : GS 2 : International Relations

दक्षिण एशिया की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान ने हाल ही में बांग्लादेश के साथ उच्चस्तरीय वार्ता शुरू की है, जो पिछले 13 वर्षों में पहली बार हुआ। यह पहल उस शून्य को भरने का प्रयास है, जो भारत-बांग्लादेश संबंधों में आई दूरी के कारण बना है। ऐसे समय में जब चीन भी सक्रिय रूप से क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित कर रहा है, भारत के लिए अपनी कूटनीति को पुनः सशक्त बनाना चुनौतीपूर्ण हो गया है।

मुख्य विश्लेषण

1. पृष्ठभूमि

- भारत और बांग्लादेश के संबंध विशेषकर शेख हसीना के शासनकाल (2009–2024) में अत्यधिक प्रगाढ़ रहे। दोनों देशों ने आतंकवाद-रोधी कदमों, संपर्क-सुविधाओं और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग किया।
- वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते 1971 के मुक्ति संग्राम, युद्ध अपराध मुकदमों और ढाका की ओर से मुआवज़ा व औपचारिक माफी की माँगों के कारण तनावपूर्ण बने रहे।

2. पाकिस्तान की नई पहल

- पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार की ढाका यात्रा ने एक नये दौर की शुरुआत की है। इस दौरान वीज़ा सुविधा, सीधी उड़ानों, छात्रवृत्तियों और व्यापार को बढ़ावा देने पर सहमति बनी।
- चीन ने भी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए त्रिपक्षीय संवाद (पाकिस्तान-बांग्लादेश-चीन) का आयोजन किया।
- प्रतीकात्मक रूप से यह पाकिस्तान की वापसी का संकेत है, ऐसे समय में जब बांग्लादेश शेख हसीना के बाद अपनी विदेश नीति को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है।

3. भारत की स्थिति और चिंताएँ

- यद्यपि प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से मुलाक़ात की है, लेकिन भारत की सक्रियता अपेक्षाकृत कम दिखाई देती है।
- भारत की मुख्य चिंताएँ:
 - खबरें कि पाकिस्तानी राजनियकों ने **जमात-ए-इस्लामी छात्र** संगठनों को हसीना-विरोधी प्रदर्शनों में समर्थन दिया।
 - ढाका और इस्लामाबाद के बीच सैन्य एवं खुिफया संपर्कों की संभावना।

Friends and foes

Pakistan is filling the void created by the alienation of India from Bangladesh

n the first such visit in 13 years, Pakistan's Foreign Minister Ishaq Dar travelled to Dhaka over the weekend to meet with members of the Bangladeshi interim government, headed by Muhammad Yunus, and hold talks with his counterpart, Touhid Hossain. Ties had been tense since 2009, when Sheikh Hasina came to power, and under strain over the prosecution of those who colluded with Pakistan during the 1971 liberation war - and the assassination of her father Sheikh Mujibur Rahman and most of her family in 1975. In 2015, Bangladesh demanded the expulsion of a Pakistani diplomat over links to a terror group and recalled its High Commissioner to Islamabad after Pakistan protested the hanging in Bangladesh of those found guilty of collusion in 1971. Although the two nations subsequently restored envoys, they began to repair ties after Ms. Hasina's ouster last August. The process was also nudged by China, which convened a trilateral mechanism with Bangladesh and Pakistani officials in Kunming. In Dhaka, there was agreement to restore visa facilitation for diplomats, have direct flights, grant scholarships for Bangladeshi students and ways to enhance trade from current lows of less than a billion dollars. However, the Yunus government has refused to move on decades-old Bangladeshi demands for reparations from Pakistan. These include a formal apology for the genocide in 1971 perpetrated by Pakistani forces, financial compensations and the repatriation of thousands of "Stranded Pakistanis" or Urdu-speaking Muhajirs who had migrated there after Partition and still held allegiance to West Pakistan. While meeting Mr. Dar, Mr. Yunus also called for strengthening regional cooperation, including a revival of the SAARC process. India has eyed the thaw in Islamabad-Dhaka ties with some suspicion, given reports that Pakistani diplomats supported Jamaat-e-Islaami student activists during the anti-Hasina protests last year. Of greater concern has been military and intelligence contacts.

While there is no question that New Delhi has cause to feel cut out and bruised by the newfound bonhomie between an erstwhile ally and a long-time foe, it is time that South Block adopts a more realistic prism. Pakistan is stepping into the breach caused by the strain in India-Bangladesh ties. Although Mr. Modi met Mr. Yunus in April and External Affairs Minister S. Jaishankar met Mr. Hossain on the side-lines of other international events, neither has contemplated a visit, nor has Mr. Yunus been invited. With the announcement of elections in Bangladesh, in February, New Delhi must also broaden its political engagement with political parties there, even as it nudges the Yunus government to a more inclusive process. In the absence of a stronger regional South Asian grouping, New Delhi has a difficult task in holding sway over bilateral ties between any of its neighbours, especially Bangladesh and Pakistan.





• यह स्थिति भारत की "पड़ोसी पहले" नीति के लिए चुनौती है।

4. क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य

- बांग्लादेश ने **सार्क (SAARC) पुनर्जीवन** की माँग की है, जबकि भारत ने पाकिस्तान की अड़चनों के कारण इसे हाशिए पर डाला हुआ है।
- पाकिस्तान और चीन की संयुक्त पहल भारत की क्षेत्रीय प्राथमिकता को कमजोर कर सकती है।
- यह शून्य दिखाता है कि मज़बूत क्षेत्रीय मंच के अभाव में भारत की प्रभावशीलता सीमित हो जाती है।

आगे की राह

- राजनीतिक संवाद का विस्तार: भारत को सिर्फ अंतरिम सरकार ही नहीं बल्कि विपक्षी दलों से भी संवाद बनाए रखना चाहिए, विशेषकर चुनावी समय में।
- आर्थिक व संपर्क सहयोग: बांग्लादेश को प्रत्यक्ष लाभ पहुँचाने वाली व्यापार और अवसंरचना परियोजनाओं को और गित देना।
- उच्चस्तरीय यात्राएँ: भारतीय नेतृत्व की ढाका यात्रा से दूरी की धारणा टूटेगी।
- क्षेत्रीय नीति: सार्क में रचनात्मक पुनःसक्रियता या वैकल्पिक मंचों (जैसे बिम्सटेक) को अधिक राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ आगे बढ़ाना।

निष्कर्ष

पाकिस्तान-बांग्लादेश के बीच बढ़ती नज़दीकी दक्षिण एशियाई राजनीति की बदलती तस्वीर को दर्शाती है। यद्यपि 1971 से जुड़ी कई माँगें अब भी अनसुलझी हैं, फिर भी पाकिस्तान का यह प्रयास भारत-बांग्लादेश संबंधों में आई दरारों को उजागर करता है। भारत के लिए आवश्यक है कि वह अधिक सक्रिय, समावेशी और क्षेत्रीय रूप से समन्वित कूटनीति अपनाए, ताकि दक्षिण एशिया में उसकी केंद्रीय भूमिका बनी रहे।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: पाकिस्तान-बांग्लादेश संबंधों में हालिया निकटता दक्षिण एशियाई भू-राजनीति में बदलाव का संकेत है। भारत की विदेश नीति पर इसके प्रभावों का विश्लेषण कीजिए तथा बताइए कि भारत को अपने रणनीतिक हितों की रक्षा हेतु कौन-से कदम उठाने चाहिए।" (150 Words)





Page 09: GS 2: Indian Polity

हाल ही में एक विश्लेषण के अनुसार, लगभग 30% सांसद और विधायक गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। लोकसभा में ऐसे सांसदों का प्रतिशत 2009 में 14% से बढ़कर 2024 में 31% हो गया है। यह लोकतंत्र की गुणवत्ता और शासन व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है।

वर्तमान स्थिति

- संसद : 31% सांसद गंभीर आपराधिक मामलों में लिप्त। सबसे अधिक तेलंगाना (71%), बिहार (48%), और उत्तर प्रदेश (34 सांसदों के साथ सर्वाधिक संख्या)।
- विधानसभाएँ : 29% विधायक ऐसे मामलों में शामिल। आंध्र प्रदेश (56%) और तेलंगाना (50%) सबसे आगे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संख्या विधायक)।

राजनीतिक दल:

- भाजपा → 63 सांसद और 436 विधायक गंभीर मामलों में।
- कांग्रेस → 32 सांसद और 194 विधायक।
- राजद → 100% (4 सांसद) और 62% विधायक अपराध मामलों में।
- टीडीपी \rightarrow 61% विधायक आरोपित।

About 30% of MPs and MLAs face serious criminal cases

In the Lok Sabha, the share of MPs facing serious criminal charges has more than doubled since 2009

DATA POINT

The Hindu Data Team

n analysis of MPs and MLAs across India shows that 31% of MPs and 29% of have declared serious crimi-arges against them. As the is was conducted immenentary elections, and Assembly lections in each State, it does not

ections in each state, it does not leftect some of the current set of IPs and MLAs. A serious criminal charge in-tudes offences where the maxi-tum punishment is five years or tore, or those that are non-baila-

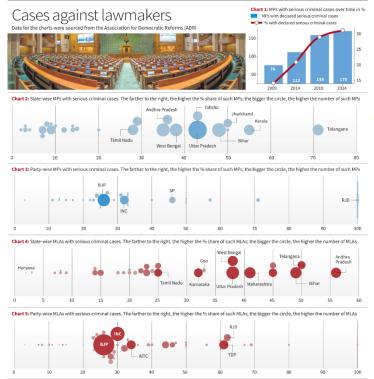
:. In the Lok Sabha, the share of Ps facing serious criminal cases s more than doubled, from 14% 2009 to 31% in 2024 (Chart 1). the Assemblies, the share was % in 2024, which accounts for

roportions were higher: all four IPs of the Rashtriya Janata Dal

MPs of the Rashtriya Janata Dal (RJD) had serious cases against them (Chart 3).

Andhra Pradesh had the highest share of MLAs with serious criminal cases at 56%, followed by Te-langana (50%). U.P. recorded the highest absolute number (154 MLAs or 38% of its total) (Chart 4). While GFs of the Telugu Desan Party (TDP)'s MLAs faced serious cases, 62% of the RID's did. The BJP, which has the largest presence in Assemblies, accounted

for 436 MLAs (26%) with serious cases, followed by the Congress



प्रभाव

- लोकतांत्रिक कमी अपराधी जनप्रतिनिधि जनता के विश्वास को कमजोर करते हैं।
- नीतिगत अपहरण राजनीति अपराधियों के लिए संरक्षण का साधन बनती है।
- कानून का क्षरण कानून बनाने वाले ही कानून तोडें तो संस्थाएँ कमजोर होती हैं।
- 4. **शासन पर प्रभाव** नीतिगत बहस की जगह संरक्षण और संरक्षणवाद बढ़ता है।





5. **मतदाता विरोधाभास** – जागरूकता के बावजूद जातीय/सामुदायिक जुड़ाव व धन-बल के कारण मतदाता ऐसे उम्मीदवार चुन लेते हैं।

न्यायिक एवं संस्थागत हस्तक्षेप

- सुप्रीम कोर्ट
 - 2002: प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा अनिवार्य।
 - 2013: दोषसिद्ध जनप्रतिनिधियों की सदस्यता समाप्त।
 - 2018: राजनीतिक दलों को अपराध पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों की जानकारी प्रकाशित करना अनिवार्य।
- चुनाव आयोग : गंभीर मामलों में आरोप तय होने के बाद ही उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने की सिफारिश।
- विधि आयोग (244वीं रिपोर्ट) : गंभीर मामलों में आरोप तय होते ही चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध की सिफारिश।

आगे की राह

- 1. कानूनी सुधार जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन, गंभीर मामलों में आरोप तय होते ही अयोग्यता।
- 2. **चुनावी सुधार** राज्य पोषित चुनाव, व्यय सीमा कड़ाई से लागू, राजनेताओं के मामलों की फास्ट-ट्रैक अदालतें।
- 3. **राजनीतिक इच्छाशक्ति** दलों को स्वेच्छा से अपराधी उम्मीदवारों को टिकट न देना।
- 4. मतदाता जागरूकता NOTA को सशक्त करना, नागरिक समाज व मीडिया की भूमिका।
- 5. संस्थागत मजबूती स्वतंत्र चुनाव आयोग, पुलिस सुधार और जांच एजेंसियों का राजनीतिकरण खत्म।

निष्कर्ष

लोकसभा में अपराधी सांसदों का अनुपात 2009 के 14% से 2024 में 31% तक पहुँच जाना लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरे का संकेत है। केवल न्यायिक आदेश पर्याप्त नहीं होंगे; राजनीतिक दलों और मतदाताओं दोनों को अपराधी तत्वों को अस्वीकार करना होगा। यदि भारत को स्वच्छ, पारदर्शी और जवाबदेह लोकतंत्र बनाना है तो राजनीति के अपराधीकरण को रोकना राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना होगा।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न : भारतीय राजनीति में बढ़ता अपराधीकरण लोकतंत्र की गुणवत्ता और शासन व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है।" उपरोक्त कथन के आलोक में हालिया आंकड़ों का विश्लेषण कीजिए तथा राजनीति के अपराधीकरण को रोकने हेतु आवश्यक सुधारों का सुझाव दीजिए। (250 शब्द)





Page: 08 Editorial Analysis

India-Japan ties — old partners, new priorities

rime Minister Narendra Modi's visit to Japan and China, that begins from August 29, comes at a time of flux in global geopolitics. While there is a tentative easing of tensions between India and China after years of strain, there is also growing uncertainty about New Delhi's ties with Washington as the Trump administration seems to be doing everything in its power to push India away. Thus, Mr. Modi's engagement in Tokyo carries weight well beyond the bilateral.

Japan's major investment plan

At the heart of the visit lies Japan's announcement of a ¥10 trillion (about \$68 billion) investment plan in India to be spread over the next decade. This pledge, among the most ambitious Tokyo has ever made to New Delhi, is designed to boost the infrastructure, manufacturing, clean energy, and technology partnership. It signals Japan's long-term stake in India's growth story at a time when many global investors remain cautious about China. The fact that Japan is also investing in the next-generation EIO series Shinkansen for the Mumbai-Ahmedabad high-speed rail corridor.

Mumbai-Ahmedabad high-speed rail corridor reflects economic collaboration alongside Tokyo's willingness to transfer cutting-edge technology to India.

On the strategic front, the two countries are expected to revise the 2008 Joint Declaration on Security Cooperation, reorienting their security and defence partnership in accordance with contemporary realities. The proposed Economic Security Initiative – it covers semiconductors, critical minerals, pharmaceuticals, and clean energy – anchors Japan more firmly within India's quest for diversified supply chains. Also significant is the upgrade of their digital partnership, which is now expected to cover artificial intelligence and startup ecosystems. These initiatives place India-Japan ties at the forefront of technological and security



Harsh V. Pant

is Vice-President – Studies and Foreign Policy at the Observer Research Foundation and Professor of International Relations at King's College London



Pratnashree Basu

is an Associate Fellow–Indo-Pacific at the Observer Research Foundation

The Prime Minister's Japan visit highlights India's steady strategic intent, with signals to China and the US cooperation in Asia, reinforcing their shared commitment to a free, open, and rules-based Indo-Pacific.

The U.S. factor, a case of strategic balancing

The timing of the visit is important. After the Tokyo meeting, Mr. Modi is scheduled to attend the Shanghai Cooperation Organisation summit in Tianjin, China. Bilateral ties, though scarred by the 2020 Galwan clash, are demonstrating tentative signs of stabilisation with the resumption of direct flights, visa relaxations, and trade facilitation efforts. The visit, from Tokyo to Beijing in a single week, reflects a strategic balancing in many ways. First, it underscores India's ability to engage with a trusted strategic partner and a neighbouring competitor without allowing one relationship to dictate the other. Second, it signals that India can compartmentalise. With Tokyo, the focus is on advancing economic security, defence cooperation, and Indo-Pacific stability, With Beijing, the emphasis will likely be on managing tensions, exploring limited confidence-building measures, and keeping communication lines

The balancing becomes even more consequential against the backdrop of Mr. Trump's unpredictability, which has cast a shadow on the reliability of the United States as a steady partner. Mr. Trump stands to unravel years of careful effort invested in building the New Delhi-Washington partnership. Successive administrations on both sides, from George W. Bush to Joe Biden, worked to transform a once-fractious relationship into a cornerstone of Indo-Pacific strategy, anchored in defence cooperation, technology sharing, and growing people-to-people ties. So far, Trump 2.0 risks eroding this progress. The Quad (India, Australia, Japan, the U.S.) too, remains essential to India's Indo-Pacific vision, but its trajectory appears rocky as U.S. engagement turns episodic. The

grouping was conceived as a platform to pool capacities among like-minded democracies, yet its momentum has always depended on Washington's willingness to commit consistently. Under Mr. Trump's second term, signals of disengagement and a narrower view of alliances risk diluting the Quad's strategic coherence. For India, Japan and Australia, this raises pressing questions about sustaining the initiative's credibility and operational depth.

Beyond economics and defence, there is a broader political signal embedded in the visit. By stepping up its engagement with India, Japan is not just diversifying its economic footprint but is also reinforcing the idea that dedicated long-term cooperation can deliver tangible outcomes.

The message

The Tokyo visit is thus less about short-term diplomatic outcomes and more about signalling steady strategic intent – that India is willing to keep channels with Beijing open, prepared to navigate U.S. unpredictability, and determined to deepen enduring partnerships with like-minded powers in the region. Japan's commitments also reinforce India as one of its most reliable partners in navigating the challenges of the Indo-Pacific, from economic resilience to maritime security.

The visit will highlight one of the most enduring features of Indian diplomacy in recent years: flexibility without losing strategic clarity. In a phase of protracted geopolitical uncertainty, it is Japan that emerges as India's anchor partner. Washington's commitment is wavering under Trump's short-sightedness, while Beijing remains a competitor whose gestures of normalisation cannot yet ease underlying mistrust. Tokyo offers consistency, resources and a shared strategic outlook rooted in democratic values and a free and open Indo-Pacific. Therefore, the visit to Japan is not just about consolidating an old partnership. It is about recognising where India's most dependable ballast lies.

GS. Paper 02 International Relations

UPSC Mains Practice Question: भारत और जापान के बीच "विशेष सामरिक एवं वैश्विक साझेदारी" है, जिसमें आर्थिक, सामरिक और इंडो-पैसिफिक आयाम शामिल हैं। भारत की प्रगति और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए इस साझेदारी के महत्व पर चर्चा कीजिए। (150 words)





Context:

भारत और जापान के संबंध एशिया की रणनीतिक राजनीति और आर्थिक सहयोग के सबसे स्थिर स्तंभों में से एक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया जापान यात्रा ऐसे समय में हुई है जब वैश्विक भू-राजनीति अनिश्चितता से गुजर रही है। अमेरिका की नीतिगत अनिश्चितता, चीन के साथ संबंधों में तनाव और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति-संतुलन की चुनौतियाँ भारत-जापान साझेदारी को और महत्वपूर्ण बना देती हैं।

मुख्य विश्लेषण

1. आर्थिक सहयोग और निवेश

- जापान ने भारत में अगले दशक में लगभग 10 ट्रिलियन येन (लगभग 68 अरब डॉलर) निवेश की घोषणा की है।
- यह निवेश बुनियादी ढाँचे, विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा और तकनीकी साझेदारी को गित देगा।
- बुलेट ट्रेन परियोजना (मुंबई-अहमदाबाद) में जापान की भागीदारी केवल आर्थिक सहयोग ही नहीं बल्कि उन्नत तकनीक के हस्तांतरण का भी प्रतीक है।

2. रणनीतिक और सुरक्षा साझेदारी

- 2008 के संयुक्त सुरक्षा सहयोग घोषणा-पत्र को नए सिरे से परिभाषित करने की तैयारी है।
- दोनों देशों के बीच आर्थिक सुरक्षा पहल (Economic Security Initiative) सेमीकंडक्टर, दवाइयाँ, स्वच्छ ऊर्जा और महत्त्वपूर्ण खनिजों पर केंद्रित है।
- डिजिटल और AI सहयोग से यह साझेदारी 21वीं सदी की तकनीकी साझेदारी के रूप में उभर रही है।

3. अमेरिका और चीन के संदर्भ में संतुलन

- मोदी की जापान यात्रा के तुरंत बाद चीन की यात्रा इस बात का संकेत है कि भारत एक साथ साझेदारी और प्रतिस्पर्धा दोनों को संतुलित करने की नीति अपना रहा है।
- अमेरिका की नीतिगत अस्थिरता (ट्रंप 2.0 की अनिश्चितता) के बीच भारत-जापान संबंध विश्वसनीय और स्थिर विकल्प के रूप में उभर रहे हैं।
- काड (भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया) की उपयोगिता बनी हुई है, लेकिन अमेरिका की अनिश्चित भूमिका के कारण इसकी रणनीतिक विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। ऐसे में भारत और जापान इस पहल को मजबूत बनाए रखने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

4. राजनीतिक संदेश

- जापान के निवेश और सहयोग से यह संकेत जाता है कि दीर्घकालिक साझेदारी ठोस परिणाम ला सकती है।
- यह भारत की विदेश नीति की लचीलापन के साथ स्पष्ट रणनीतिक दृष्टि को दुर्शाता है।





भारत–जापान संबंध ऐतिहासिक संबंध

- बौद्ध धर्म और सांस्कृतिक आदान-प्रदान।
- टैगोर-ओकाकुरा संवाद।
- स्वतंत्रता के बाद (1947 के पश्चात): जापान ने भारत के औद्योगिकीकरण में मदद की (मारुति प्रोजेक्ट, मेट्रो परियोजनाएँ, दिल्ली-मेट्रो के लिए JICA ऋण)।

आर्थिक सहयोग

- जापान भारत का 5वाँ सबसे बड़ा निवेशक है।
- प्रमुख परियोजनाएँ :
 - बुलेट ट्रेन (मुंबई-अहमदाबाद)
 - दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर
 - चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर
- 2025 : जापान ने 10 ट्रिलियन येन निवेश (इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, स्वच्छ ऊर्जा) की घोषणा की।

रणनीतिक सहयोग

- 2014 : "विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी"।
- 2008 : सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा।
- रक्षा अभ्यास :
 - JIMEX (नौसैनिक अभ्यास)
 - मालाबार (क्वांड भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया)।
- 2+2 वार्ता : रक्षा व विदेश मंत्रियों का संवाद।

इंडो-पैसिफिक सहयोग

- दोनों देश मुक्त और खुला इंडो-पैसिफिक (FOIP) दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध।
- सप्लाई चेन रेजिलियंस, सेमीकंडक्टर सहयोग में साझेदारी।
- जापान : काड का मजबूत सदस्य।
- भारत : अमेरिका, जापान और चीन के बीच संतुलन की नीति अपनाता है।





चुनौतियाँ

- भारत–जापान व्यापार अभी भी क्षमता से कम (~22 अरब डॉलर, 2024)।
- चीन कारक भारत की बीजिंग के साथ संतुलनकारी नीति को लेकर जापान सतर्क।
- परियोजनाओं का धीमा क्रियान्वयन (विशेषकर बुलेट ट्रेन में विलंब)।

आगे की राह

- आर्थिक सुरक्षा सहयोग को गहराना AI, सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ मिनरल्स।
- इन्फ्रास्ट्क्चर परियोजनाओं की गति तेज करना।
- रक्षा प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और संयुक्त उत्पादन को बढ़ावा।
- साझेदारी को इंडो-पैसिफिक स्थिरता का आधार स्तंभ बनाना।

निष्कर्ष

भारत-जापान संबंध केवल आर्थिक और रक्षा साझेदारी तक सीमित नहीं हैं, बिल्क यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों, स्वतंत्रता और स्थिरता को मजबूत करने का साझा प्रयास है। अमेरिका की अनिश्चितता और चीन के साथ प्रतिस्पर्धा की स्थिति में, जापान भारत के लिए सबसे विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। अतः मोदी की यह यात्रा सिर्फ पुराने संबंधों को दोहराने की नहीं, बिल्क नई प्राथमिकताओं के अनुरूप उन्हें गहराई और दिशा देने की प्रक्रिया है।